RNI No. RAJHIN/2014/58645
डाक पंजीयन संख्या JAIPUR CITY/280/2015-17
e-paper : www.srushtiagronews.com

प्रदेश के लिए 14 करोड़ की 36 नई परियोजनाएं मंजूर

सृष्टि एग्रो

वर्ष -4 | अंक-18 | जयपुर 1 से 15 दिसम्बर 2017 | मूल्य - 2 रुपए | पाक्षिक | पृष्ठ-8

किसानों को समय पर मिले फसल बीमा योजना का पैसा :राजे

जयपुर (कासं)। मुख्यमंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजे ने कहा कि किसानों को फसल बीमा योजना का पैसा समय पर मिल सके, यह सुनिश्चित किया जाए। साथ ही इसके लिए राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों की जानकारी भी किसानों तक पहुंचाई जाए। उन्होंने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का ग्राम पंचायत स्तर तक व्यापक प्रचार-प्रसार करने तथा अधिक से अधिक किसानों को इस योजना से जोड़ने के निर्देश भी दिए।

श्रीमती राजे राजविकास की छठी बैठक के दौरान मुख्यमंत्री कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए विभिन्न विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिवों, प्रमुख शासन सचिवों, सचिवों एवं जिला कलक्टरों को सम्बोधित किया। प्रमुख सचिव, कृषि नीलकमल दरबारी ने बताया कि किसानों को जागरूक करने के लिए तहसील स्तर पर कार्यशालाओं का आयोजन, वेब पोर्टल का निर्माण तथा समन्वय के लिए बैंक व बीमा कम्पनियों के अधिकारियों के साथ समय-समय पर बैठकों का आयोजन भी किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान (एमजेएसए) के कारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश की एक अलग पहचान कायम हुई है। उन्होंने जिला कलक्टरों को निर्देश दिए कि जल संरक्षण के क्षेत्र में राजस्थान ने जो गति हासिल की है उसे बनाए रखें और एमजेएसए के तीसरे चरण के तय लक्ष्यों को समय पर पूरा करें। प्रदेश की मण्डरायल और गागरीन पेयजल परियोजनाओं पर विशेष ध्यान देकर इनके कामों में तेजी लाई जाए, ताकि लोगों को समय पर पानी मिल सके। उन्होंने प्रमुख शासन सचिव पीएचईडी रजत मिश्र को निर्देश दिए कि नागौर लिफ्ट कैनाल पेयजल परियोजना और चम्बल-भीलवाड़ा जलप्रदाय परियोजना जैसे **(शेष पेज दो पर)**

राज्य सरकार ने कृषि क्षेत्र में खर्च किए 9 हजार 551 करोड़ रुपए : सैनी

जयपुर (कासं)। कृषि मंत्री प्रभुलाल सैनी ने कहा कि राज्य सरकार ने कृषि और कृषक कल्याण में कोई कसर नहीं छोड़ी है। सरकार ने मात्र चार साल में कृषि के क्षेत्र में 9 हजार 551 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। हमारी सरकार ने चार वर्ष में ही गत सरकार की तुलना में 62 फीसदी से अधिक राशि खर्च कर किसानों को संबल दिया है। इसके अलावा एक करोड़ 32 लाख किसानों को 6 हजार करोड़ रुपये से अधिक कृषि आदान सहायता के रूप में दिए गए। सैनी को राज्य कृषि प्रबंध संस्थान, दुर्गापुरा में सरकार के चार वर्ष पूर्ण होने पर मीडिया से बातचीत कर रहे थे।

कृषि और पशुपालन विभाग में होंगी 4 हजार 136 पदों पर भर्तियां: सैनी ने बताया कि कृषि व पशुपालन विभाग में कुल 4 हजार 136 पदों पर भर्तियां की जाएंगी। उन्होंने बताया कि कृषि विभाग द्वारा 750 कृषि पर्यवेक्षक, 409 तकनीकी एवं अधीनस्थ **(शेष पेज दो पर)**

गेहूं के लिए आया नया बीज, रेतीली जमीन में भी उपयुक्त

श्रीगंगानगर (विसं)। गेहूं के लिए सरकारी स्तर पर नया बीज आया है, जो बदलते मौसम में भी उत्पादन और बेहतर क्वालिटी देगा। इतना ही नहीं रेतीली जमीन पर भी इस बीज से उत्पादन होगा। अनेक जगहों पर ट्रायल के बाद इसकी खूबियां सामने आई। इस किस्म में फसल को बीमारियों से लड़ने की क्षमता भी है। सर्द-गर्म मौसम भी इसे ज्यादा प्रभावित नहीं करेगा। राज्य बीज निगम ने इस साल किसानों के लिए गेहूं का नया बीज उपलब्ध कराया है। इसमें राज-1482 एवं राज-3077 जैसे गुण हैं। यही नहीं दोनों के विकल्प के तौर पर इलाके में बोया जा रहा राज-4238 ऐसा बीज है जो रेतीली भूमि में भी अच्छा उत्पादन दे सकता है। इसके कई जगह पर ट्रायल होने के बाद पिछले साल ही पैकेज में लिया है। राज-4238 के ब्रीडर वैज्ञानिक डॉ. अजीतसिंह ने बताया कि हालांकि यह किस्म 2013 में गई थी, लेकिन किसी कारणवश रुकी हुई थी, इसे पिछले साल अनुमोदन कमेटी ने पास कर दिया है। राज्य बीज निगम श्रीगंगानगर में उपलब्ध राज-4238 किस्म के बीज को पकाव में 110 से 115 दिन लगते हैं। अगर पक्की दोमट मिट्टी हो तो 42-46 क्विंटल प्रति हैक्टेयर (चार बीघा) उपज हो सकती है। इसे पकाने के लिए कम से कम चार-पांच बार पानी देना होता है। राजस्थान बीज निगम श्रीगंगानगर के एरिया मैनेजर शिवजीराम कटारिया ने बताया कि **(शेष पेज दो पर)**

सम्पादकीय

किसान का नुकसान

अगर खाद्य तेल पर आयात शुल्क में बढ़ोतरी करने और दालों पर निर्यात प्रतिबंध समाप्त करने का इरादा इन जिंसों की कमजोर कीमतों को बढ़ाकर किसानों को लाभ पहुंचाने का है तो इससे कोई फायदा होता नहीं दिखता। इन फसलों का ज्यादातर हिस्सा खरीफ के मौसम में उत्पादित होता है और उसकी कटाई पहले ही हो चुकी है। किसान औनेपौने दाम पर उनका सौदा भी कर चुके हैं। किसानों को इसका लाभ तब मिलता जबकि ये निर्णय बुआई के पहले लिए गए होते। इससे ये इन फसलों का रकबा बढ़ा सकते थे या कम से कम फसल कटाई के समय ही उनको इनकी बेहतर कीमत मिल पाती। फिलहाल कीमतों में किसी भी तरह की बढ़ोतरी व्यापार और प्रसंस्करण उद्योग को लाभान्वित करेगी और किसानों की हालत जस की तस रहेगी। हकीकत में तिलहन और दलहन इकलौती ऐसी फसल नहीं हैं जिनकी कीमतों में गिरावट आई है। अधिकांश कृषि जिंसों की कीमतें पिछले साल हुए बंपर उत्पादन के बाद से ही न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) से नीचे रही हैं। कुछ मामलों में कीमतें उत्पादन मूल्य से भी कम हो गईं। कीमतों में आई यह गिरावट इस वर्ष भी जारी रही, हालांकि उड़द और कपास को छोड़कर अधिकांश खरीफ फसलों का उत्पादन या तो पुराने स्तर पर बरकरार रहा या गिरा। इसका दोष सरकार की गलत कृषि मूल्य निर्धारण नीतियों को भी जाता है जो मोटे तौर पर मुद्रास्फीति प्रबंधन से संबंधित हैं। इसे गत वर्ष 2.3 करोड़ टन की जरूरत के मुताबिक उत्पादन के बावजूद 50 लाख टन दालों के आयात से भी समझा जा सकता है। जरूरत से ज्यादा आपूर्ति ने कीमतों को प्रभावित किया। तकरीबन 180 किसान संगठनों के गठबंधन ने दिल्ली में किसान मुक्ति संसद का आयोजन किया और उपज की अच्छी कीमत और ऋण में रियायत की मांग की। कमजोर कीमतों के चलते किसानों को करीब 36,000 करोड़ रुपये का नुकसान होने का अनुमान है। बताया जाता है कि यह आकलन करते वक्त एमएसपी और मौजूदा थोक कीमतों को ही ध्यान में रखा गया है। बहरहाल, वास्तविक नुकसान ज्यादा हो सकता है क्योंकि अनेक किसानों को अपनी उपज को आधिकारिक थोक कीमतों से कम में बेचना पड़ा क्योंकि उनको अपनी नकदी संबंधी जरूरतों को पूरा करना था। ऐसे में यह उम्मीद करना बेमानी है कि अपेक्षाकृत देरी से उठाए गए नीतिगत कदम किसानों की समस्या हल कर पाएंगे। सही मायनों में जरूरत यह है कि कृषि मूल्य और व्यापार को लेकर स्थिर नीतियां बनाई जाएं। इसमें आयात और निर्यात भी शामिल हैं। इसमें बाजार की मांग और कीमतों के अनुरूप उत्पादन करने की इजाजत भी शामिल है। फिलहाल नीतिगत अनिश्चितताओं के कारण ऐसा नहीं हो पा रहा। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग ने अपनी कई रिपोर्ट और चर्चा पत्रों में इस बात पर जोर दिया है। इस दिशा में कुछ उम्मीद सरकार के हालिया निर्णय से भी उपजती है जहां उसने एक फॉर्मूला विकसित करने की बात कही है ताकि कृषि आयात और निर्यात पर शुल्क बढ़ाने और घटाने का काम थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर किया जाए। यह विचार काफी हद तक तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन द्वारा 1980 के दशक के मध्य में अपनाए तरीके के अनुरूप ही है। इसकी वजह से देश उस दशक के अंत तक खाद्य तेल के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो सका। उस योजना को छोड़ने और बाजार की उपलब्धता और मूल्यों की असामान्यता को लेकर तगड़ी प्रतिक्रिया के साथ सरकार ने पारदर्शी नीति व्यवस्था का लाभ गंवा दिया। आश्चर्य नहीं कि घरेलू तेल की जरूरतों के मामले में हमारी आयात निर्भरता एक बार फिर 70 फीसदी पर पहुंच गई। ऐसे में केवल आयात निर्यात शुल्क से छेड़छाड़ से काम नहीं चलेगा।

चना में समन्वित कीट-रोग प्रबंधन

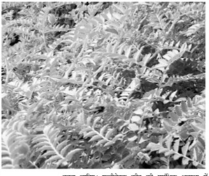

भूमिगत कीट: सुषुप्तावस्था में पड़े कीटों के अंडे वशंकु, खरपतवार तथा फसल के अवशेषों को नष्ट करने के लिए गर्मियों में खेत की गहरी जुताई करनी चाहिए।

कीट रोग प्रतिरोधी किस्में: बुवाई के लिये काम में लेना चाहिए। जैसे-आर.एस. सी.-44 (उखटा रोग के प्रति मध्यम प्रतिरोधी), जी.एन.जी.-1581/गणगौर (झुलसा, जड़गलन एवं एस्कोकाइटा ब्लाईट के प्रतिऔसतप्रतिरोधी), आर.एस. जी.-888/अनुभव (उखटा, जड़गलन एवं सूत्र कृमिरोधी), सी.एस.जे.डी.-884/आकार (उखटा, जड़गलन रोगों के प्रति मध्यम प्रतिरोधी एवं फली छेदक कीटों से कम प्रभावित), आर.एस.जी.-945/आसार (फली छेदक कीटों से कम प्रभावित व सूत्रकृमि प्रतिरोधी), आर.एस.जी.के.-6/आसार (फली छेदक कीटों से कम प्रभावित, जड़गलन व सूत्रकृमि रोग प्रतिरोधी), आर.एस.जी.-896/अर्पण (उखटा, जड़गलन (शुष्क एवं काली), बी.जी.एम. स्टन्टवाइरसरोगप्रतिरोधी) आर.एस.जी.-991/अपर्णा (चने की प्रमुख बीमारियों हेतु प्रतिरोधी)।

बीज को बुवाई से पूर्व थाइरम 3 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज अथवा ट्राईकोडर्मा 4-6 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करना चाहिए।

अन्तराशस्य के रूप में चने की 7 लाईनों के बाद 2 लाईन सरसों की बुवाई करना चाहिए।

दो से तीन वर्ष तक बिना दाल वाली फसलों जैसे मक्का, गेहूं आदि के साथ फसल चक्र अपनाना चाहिए।

खेत में चिड़ियां, मैना आदि पक्षियों को बैठने के लिये लकड़ी के अड्डे बनाये जिससे ये कीटों को खाकर नष्ट कर सकें। लाइटट्रेप की सहायता से कीड़ों को नष्ट करें। राष्ट्रीय समेकितनाशी जीव प्रबंधन केंद्र, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली के वैज्ञानिकों द्वारा लाईटट्रेप को डिजाइन व अनुमोदित किया गया है, यह हानिकारक कीटों को नष्ट करने के साथ-साथ फसलों के मित्रकीटों को सुरक्षित कर उनका संरक्षण करता है, साथ ही फसलों के उत्पादन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कृषि विभाग द्वारा इस पर अनुदान भी देय है।

फेरोमोनट्रेप की सहायता से नर पतंगों को पकड़ कर नष्ट करना चाहिए। फलीछेदक कीट की प्रारंभिक अवस्था में एन.पी.वी. 250 एल.ई. प्रति हेक्टर की दर से 10-15 दिन के अंतराल पर तीन बार उपयोग करना चाहिये। कप्पोलिटिस क्लोरायडी नामक परजीवी 1.0-2.0 लाख प्रति हेक्टर की दर से 3-5 बार उपयोग करना चाहिये। कीटों की प्रारंभिक अवस्था में नीम से बने कीटनाशकों का प्रयोग करना चाहिए। कटवर्मव दीमक आदि की रोकथाम हेतु भूमि उपचार करना आवश्यक है। क्विनालफॉस 1.5 प्रतिशत चूर्ण 25 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से आखिरी क्विनालफॉस 1.5 प्रतिशत चूर्ण 25 किलोप्रति हैक्टेयर की दर से आखिरी जुताई से पूर्व भूमि में मिलाना चाहिए। फलीछेदक के नियंत्रण के लिये फूल आने से पहले तथा फली लगने के बाद मेलाथियॉन 5 प्रतिशत या मिथाइल पैराथियॉन 2 प्रतिशत या कार्बोरिल 5 प्रतिशत चूर्ण का 20-25 किलो प्रति हेक्टर की दर से भुरकाव करना चाहिये। जड़गलन व उखटा रोग की रोकथाम के लिये कार्बेण्डाजिम 50 प्रतिशत डब्ल्यू.पी. 2 ग्राम या थाइरम 80 प्रतिशत डब्ल्यू.पी. 2.50 ग्राम प्रतिकिलो बीज की दर से उपचारित करना चाहिए अथवा 6-8 ग्रामट्राईकोडर्मा मित्र फफूंद का प्रतिकिलो बीज की दर से उपचार करना चाहिए। झुलसा रोग के लक्षण दिखाई देन पर मेन्कोजेब 75 प्रतिशत डब्ल्यू.पी. 0.2 प्रतिशत (2 ग्राम प्रति लीटर पानी) या कॉपरऑक्सीक्लोराइड 50 प्रतिशत डब्ल्यू.पी. 0.3 प्रतिशत (3 ग्राम प्रति लीटर पानी) या घुलनशील गंधक 80 प्रतिशत डब्ल्यू.पी. 0.2 प्रतिशत (2 ग्राम प्रति लीटर पानी) के घोल का छिड़काव करना चाहिए।

पेज 1 का शेष...

किसानों को समय पर...

महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स के शेष कार्य को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए इंजीनियरों को विशेष जिम्मेदारी दी जाए।

ग्राम के एमओयू की प्रगति की समीक्षा की: श्रीमती राजे ने जयपुर तथा कोटा में आयोजित ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट के दौरान हुए विभिन्न एमओयू की प्रगति की समीक्षा भी की। उन्होंने प्रमुख शासन सचिव कृषि से कहा कि ग्राम के एमओयू धरातल पर लाने के लिए जिला कलक्टरों से निरन्तर समन्वय और संवाद बनाकर पानी और भूमि आवंटन सम्बन्धी मुद्दे हल किए जाएं।

राज्य सरकार ने कृषि क्षेत्र...

सेवा के पदों पर और पशुपालन विभाग द्वारा 900 पशु चिकित्सा अधिकारी तथा 2077 पशुधन सहायकों के पदों पर भर्ती की जायेगी। उन्होंने बताया कि गत चार वर्षों में कृषि विभाग द्वारा कृषि पर्यपेक्षक के 2235 और तकनीकी एवं अधीनस्थ सेवा के 643 पदों पर भर्ती की गई। इसके साथ ही पशुपालन विभाग द्वारा 1782 पशुधन सहायक और 445 पशु चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती की गई।

प्रदेश में स्थापित होंगे 2652 कस्टम हायरिंग सेंटर: कृषि मंत्री ने बताया कि प्रदेश के लघु एवं लघु सीमान्त कृषकों को कृषि यंत्र किराये पर उपलब्ध कराने के लिए आगामी तीन वर्षों में 2652 कस्टमर हायरिंग सेंटर स्थापित किए जाएंगे। वर्ष 2017-18 में 750 कस्टम हायरिंग सेन्टर स्थापित किये जायेंगे हैं।

प्रत्येक ग्राम पंचायत पर खुलेगी पशु चिकित्सा इकाई: सैनी ने बताया कि राज्य की प्रत्येक ग्राम पंचायत पर पशु चिकित्सा इकाई खोली जाएगी। उन्होंने बताया कि इन चार वर्षों में 2560 नवीन पशु चिकित्सा उपकेन्द्र स्वीकृत किये जा चुके है तथा 540 नवीन पशु चिकित्सा उपकेन्द्रों का खोला जाना प्रक्रियाधीन है।

राज्य को मिला कृषि कर्मण पुरस्कार: राजस्थान में गेहूं के क्षेत्र में हुए उल्लेखनीय उत्पादन और उत्पादकता वृद्धि के लिए भारत सरकार द्वारा वर्ष 2014-15 के लिए कृषि कर्मण पुरस्कार प्रदान किया गया। सोलर पम्प सैट स्थापित करने में राजस्थान देश में पहले स्थान पर है। इसके लिए भारत सरकार के नवीन एवं नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा सम्मानित किया गया।

ग्राम के माध्यम किसानों को उन्नत तकनीक से कराया रूबरू : कृषि मंत्री ने बताया कि किसानों को उन्नत कृषि तकनीक से रूबरू करवाने के लिए जयपुर, कोटा और उदयपुर में ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट 'ग्राम' का आयोजन किया गया। इनमें लगभग 2 लाख किसानों द्वारा भाग लिया गया। ग्राम आयोजनों में कृषि और सम्बद्ध क्षेत्र के निवेशकों से लगभग 6 हजार करोड़ रुपये के 78 एमओयू किए गए। इन एमओयू के धरातल पर आने से 70 हजार 762 लोगों को रोजगार मिलेगा।

फसल बीमा के तहत 4 करोड़ एक लाख किसानों को 4994 करोड़ रुपए के बीमा क्लेम : कृषि मंत्री प्रभुलाल सैनी ने बताया कि फसल बीमा योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा गत चार वर्षों में 4 हजार 994 करोड़ रूपये के बीमा क्लेम किसानों को दिए गए। इसके अलावा पहली बार 105 करोड़ रुपए राज्य के बाढ़ प्रभावित जिलों के किसान को मिडटर्म सहायता के रूप में प्रदान किए गए हैं । उन्होंने बताया कि प्रति किसान बीमा क्लेम देने में भी राजस्थान देश में अग्रणी स्थान रखता है। इसके अलावा कृषक साथी योजना के तहत विगत चार वर्षों में 12 हजार 42 किसानों और मंडी श्रमिकों को 127 करोड़ 39 लाख रुपये की सहायता दी गई। किसान कलेवा योजना के तहत 89 लाख 38 हजार लाख व्यक्तियों को लाभान्वित किया गया।

जैतून की विश्व की पहली प्रसंस्कृत चाय बनाने वाला प्रदेश बना राजस्थान : कृषि मंत्री ने बताया कि किसानों की आय को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा फसलों के विविधीकरण पर विशेष फोकस किया जा रहा है। प्रदेश में जैतून, किनोवा, ड्रैगन फ्रूट और खजूर जैसी गैर परम्परागत फसलों का सफलतापूर्वक उत्पादन किया गया है। जैतून के क्षेत्र में तो प्रदेश आयातक से निर्यातक की श्रेणी में आ गया है। देश के 15 राज्यों और नेपाल को पौध राज्य द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही है। इसके अलावा देश की प्रथम ऑलिव रिफायनरी की स्थापना बीकानेर के लूणकरणसर में की गई और विश्व की पहली प्रसंस्कृत जैतून चाय का उत्पादन भी जयपुर के बस्सी में शुरू हो चुका है।

गेहूं के लिए आया नया बीज...

जिले के मौसम को देखते हुए उन्होंने यह किस्म जयपुर से मंगवाई है।

बदलते मौसम से लड़ने की क्षमता, पीला मोजक भी नहीं आएगा: डॉ.अजीतसिंह के मुताबिक फरवरी के आसपास अकसर मौसम में बदलाव देखने को मिलता है। मौसम कभी सर्द तो कई बार गर्म हो जाता है। इस बीज में ऐसे मौसम से लड़ने की क्षमता है। वहीं उम्मीद है कि इससे पीले मोजक की शिकायत भी नहीं आएगी। राज्य में इन दिनों लोकप्रिय किस्म 1482 और 3077 के मुकाबले राज-4238 किस्म में दोनों के गुण हैं। यह इस समय सर्वाधिक उपज वाली किस्म साबित होगी। राज-4238 जिस माहौल में तैयार की गई है।

पॉली हाऊस में शिमला मिर्च की उन्नत खेती

रामनारायण कुम्हार सूत्रकृमि विभाग
राजस्थान कृषि महाविद्यालय, उदयपुर।
महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी
विश्वविद्यालय उदयपुर (राज.)-313001

पॉली हाऊस में उगायी जाने वाली सब्जियों में शिमला मिर्च का प्रमुख स्थान है, रंगीन शिमला मिर्च की मांग शहरों, होटलों एवं शादी समारोहों में लगातार बढ़ रही है, यह अधिक लाभ देने वाली फसल है एवं इसका गुणवत्तायुक्त उत्पादन केवल पॉली हाउस में ही सम्भव हो पाता है। बाजार में रंगीन शिमला मिर्च की मांग दिनों दिन बढ़ती जा रही है, एवं निर्यात के क्षेत्र में भी इसकी सम्भावनाएँ असिमित है।

पॉली हाऊस के शिमला मिर्च की सफल खेती निम्न प्रकार से की जा सकती है।

तापमान एवं आद्रर्ता: शिमला मिर्च जलवायवीय कारकों से अत्यधिक संवेदनशील फसल हैं अत: इसकी खेती अन्य सब्जियों की अपेक्षा कठिन होती है। बीज अंकुरण के लिए उपयुक्त तापमान 24-25 से. होता है एवं अंकुरण के लिए अधिक समय लगता है। पौधों की सामान्य वृद्धि के लिए 20-25 से मृदा ताप उपयुक्त रहता है। फलस्थापन के लिए दिन का तापमान 20-22 से. एवं रात का तापमान 18 से. उपयुक्त होता है। आपेक्षित आर्द्रता 75-80 प्रतिशत वांछित होती है।

उन्नत किस्में

लाल शिमला मिर्च: बौम्बी, नन 3019, नताशा, टोरकल, महाभारत, तनवी प्लस, बचाटा।

पिली शिमला मिर्च: स्वर्णा, फिएस्टा, नन 3020, औरोवेले, यू.एस. 26, परसिलीया।

हरी शिमला मिर्च: इन्दिरा,भारत, केलिफोर्निया वन्डर, ग्रिनगोल्ड।

नर्सरी तैयार करना: किसी भी फसल के अच्छे उत्पादन के लिए सबसे आवश्यक होता है कि पौध रोग एवं कीट मुक्त होनी चाहिए। अगर प्रारम्भिक अवस्था में ही पौधों में रोग एवं कीटों का संक्रमण हो जाता है तो गुणवत्तायुक्त एवं अधिक उत्पादन सम्भव नहीं हो पाता है। अत: अच्छी एवं स्वस्थ पौध तैयार करना अति आवश्यक है। निम्नानुसार प्रो-ट्रे पौध तैयार की जा सकती है। एक हजार वर्ग मीटर क्षेत्र में शिमला मिर्च के 3000 पौधों की आवश्यकता होती है। नर्सरी उठी हुई क्यारियों अथवा प्रो-ट्रे में तैयार की जा सकती है। क्यारियों में पौध तैयार करने से कवक जनित मृदोढ़ रोगों के फैलने का अंदेशा रहता है, क्योंकि शुरूआती अवस्था में पौधे इन रोग कारकों से अति संवेदनशील होते हैं। अत: जहां तक सम्भव हो पौध प्रो-ट्रे में ही तैयार करनी चाहिए। सर्वप्रथम प्रो-ट्रे को साफ पानी से धोकर 2 घंटे धूप में सुखाना चाहिए अथवा प्रो-ट्रे का निर्जलीकरण करना चाहिए तत्पश्चात प्रो ट्रे में वर्मीकुलाइट, परलाइट एवं कोकोपिट का मिश्रण 1: 1: 2 के अनुपात में (आयतनानुसार) भरना चाहिए। इस मिश्रण में इतना पानी मिलाना चाहिए जिससे कि मिश्रण हाथ में लेकर बंधा जा सके। प्रो-ट्रे में मिश्रण करने के बाद प्रति कक्ष में एक बीज बोना चाहिए। बीज कोष्ठिका के बीचों बीच डालना चाहिए। बीजाई के तुरंत पश्चात झारे की सहायता से पानी देना चाहिए। अंकुरण के लिए तापमान एवं नमी का पर्याप्त बना रहना आवश्यक होता है, इसलिए बीजाई के बाद प्रो-ट्रे के उपर थर्माकोल अथवा पॉलीथिन ढकी जाती है, मौसम के अनुसार दो या तीन दिन बाद ढकी हुई परत हटा लेते हैं एवं प्रतिदिन एन.पी.के. 19:19:19 का एक प्रतिशत (1 किलोग्राम एन.पी.के. 100 लीटर पानी में घोल बनाकर) विलयन बनाकर पानी पिलाना चाहिए। सामान्यतया 30-35 दिन बाद पौध स्थानांतरण योग्य हो जाती है। इस अवधि में प्रो-ट्रे को जमीन के ऊपर नहीं रखना चाहिए अन्यथा पौधे की जड़े मृदा के अंदर चली जाती है एवं पौध निकालते हुए जड़े टूटने का खतरा रहता है। अत: प्रो-ट्रे को लकड़ी अथवा लोहे का स्टेण्ड बनाकर रखा जाता है।

रोपाई के लिए क्यारियाँ तैयार करना: पौध स्थानांतरण योग्य हो, उससे पहले पोली हाउस में क्यारियां अच्छे से तैयार करनी चाहिए। इसके लिए 1 मीटर चौड़ी एवं 30 सेमी ऊँची क्यारियां बनाई जाती है। क्यारियों की लम्बाई पॉली हाउस के आकार पर निर्भर करती है। क्यारियां बनाते समय दो क्यारियों के बीच 60 सेमी का पथ रखा जाता है जिससे कर्षण क्यारियों में सुविधा रहती है। तैयार क्यारियों का रोपण दो दिन पहले निर्जलीकरण किया जाता है, इसके लिए कॉँच की प्लेट (पेट्रिडिश) में 8-10 ग्राम पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल डाले जाते है तथा पूरी बेड को पॉलीथिन से ढक दिया जाता है। तत्पश्चात् प्रत्येक पेट्रिडिश में 5-7 मिली लीटर फॉर्मेलिन डाल दिया जाता है। इससे तुरंत गैस निकलती है जिससे मृदा में उपस्थित हानिकारक सूक्ष्मजीव नष्ट हो जाते है। यह गैस स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है अत: फार्मेलीन डालने के तुरन्त बाद पूरी यूनिट को कम से कम 24 घंटे के लिए बंद रखा जाता है। अगले दिन पोलीथिन हटाकर क्यारियों की खुदाई की जाती है तथा ड्रीप की लाईन बिछाकर उचित दूरी पर पौधों की रोपाई की जाती है। पौधे से पौधे की दूरी 45 सेमी रखनी चाहिए। पौधे रोपण करने से 2 घंटे पहले ड्रीप चालू कर देना अच्छा रहता है। रोपाई सम्भवतया: दोपहर बाद करनी चाहिए जिससे पौधों के मरने की सम्भावना न्यूनतम रहती है।

फर्टिगेशन: पौध स्थानान्तरण के पश्चात् अगले दिन 1 प्रतिशत एन.पी.के. 19:19:19 (1 किलोग्राम एन.पी.के. 100 लीटर पानी में घोल बनाकर) का विलयन बनाकर पौधों पर छिड़काव करना चाहिए जिससे पौधों की शुरूआती वृद्धि अच्छी होती है। तत्पश्चात् सप्ताह में एक बार एन.पी.के. एवं सूक्ष्म पोषक तत्वों का मिश्रण पौधों को ड्रिप के साथ अथवा डेऊन्चिंग करके देना चाहिए। सामान्यतया: शिमला मिर्च के लिए 250 किलो नत्रजन 125 किलो फॉस्फोरस एवं 125 किलो पोटाश प्रति हैक्टेयर की आवश्यकता है। अत: प्रति 1000 वर्ग मीटर क्षेत्र में प्रति सप्ताह 5-7 किलोग्राम जल में घुलनशील उर्वरक मिश्रण देने से पौधों की बढ़वार अच्छी रहती है एवं उपज भी अच्छी प्राप्त होती है। प्रारम्भिक चार-पांच सप्ताह 2-3 किलो एन.पी.के., 19:19:19 एवं उसके बाद धीरे-धीरे उर्वरक मिश्रण बढ़ाया जाता है। फल बनते समय सूक्ष्म पोषक तत्वों का मिश्रण जैसे एग्रोमिन अथवा बायोबिटा इत्यादि लगभग 1 किलोग्राम प्रति हजार वर्ग मीटर के हिसाब से डालना चाहिए।

पौधों का प्रशिक्षण एवं कृन्तन

40-50 दिन तक पौधों की सामान्य बढ़वार होने के बाद पौधों में ट्रेनिंग व कटिंग शुरू की जाती है। इसके लिए प्रत्येक पौधों पर केवल 2-3 शाखाओं को छोड़कर अन्य शाखाओं को हटा दिया जाता है, तथा पौधों को सूतली अथवा प्लास्टिक की रस्सियों के सहारे बढ़ाया जाता है। कृन्तन करते समय पास-पास वाली शाखाओं को एवं कमजोर शाखाओं को हटा दिया जाता है। मुख्य शाखाओं के नीचे आने वाली फुटानों को समय-समय पर हटाते रहना चाहिए। पौधों की शाखाओं को सप्ताह में एक बार प्रशिक्षण आवश्यक होता है, नई वृद्धि को सूतली के साथ लपेटकर ऊँचा रखा जाता है। टेनिंग समय पर नहीं करने से डालिया टूट जाती है एवं उत्पादन की गुणवत्ता पर प्रभाव पड़ता है।

सामान्य देखभाल एवं सावधानियाँ

फर्टिगेशन के समय विलयन का पी.एच. 6-7 एंव ई.सी. 0.01 से कम होनी चाहिए। 15-20 दिन के अंतराल पर ड्रीप लाईन के निरीक्षण करना चाहिए एवं ड्रीप जाम होने की स्थिति में फास्फोरिक अम्ल के 2-3 प्रतिशत विलयन से ड्रीप चलाना चाहिए।

▷ रोपाई के 15-20 दिन बाद खुपरी से पौधे के आस-पास बनी पपड़ी को हटाना चाहिए जिससे वायु संचार बना रहता है एवं पौधों की वृद्धि अच्छी रहती है।

▷फूल एवं फल बनते समय पौधे की वानस्पितिक वृद्धि एवं फलन में नियंत्रण कर सामंजस्य रखना अतिआवश्यक होता है। प्रत्येक शाखा पर 6-7 से अधिक फल हो तो कमजोर एवं छोटे फलों को हटाना चाहिए।

▷ मिर्च कवक जनित एवं वाइरस जनित बिमारियों से बहुत संवेदनशील फसल है। नर्सरी में जड़गलन से लेकर पर्णकुंचन एवं एन्थ्रेकनोज आदि शिमला मिर्च की फसल को पूर्णतया नष्ट करने की क्षमता रखती है। इनका समय-समय पर सही निरीक्षण एवं उपचार करते रहना चाहिए।

▷ पॉली हाउस में लगातार फसल लेने से मृदा में सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, विषेशत: केल्शियम जिसकी कमी से फलों पर काले भूरे रंग का धब्बा हो जाता है, एवं फल सड़ने लगते है, इस प्रकार के फलों को देखने से किसी कवक जनित रोग का आभास होता है, ऐसी स्थिति में 10-15 किलोग्राम प्रति 100 वर्ग मीटर के हिसाब से जिप्सम डालना चाहिए।

▷ रंगीन शिमला मिर्च की तुड़ाई करते समय ध्यान रखना चाहिए कि पूर्ण विकसित एवं रंगीन फलों की चाकू अथवा सिकेटियर की सहायता से कटाई करनी चाहिए।

▷ कभी-कभी बाजार में रंगीन शिमला मिर्च के भाव हरी शिमला मिर्च से कम भी हो सकते है, ऐसे में फलों को प्रारम्भिक अवस्था में तोड़ लेना चाहिए।

▷शिमला मिर्च के पौधे की शाखाएं सामान्यतया: कमजोर होती है, एवं फलों के भार से प्राय: टूटने की आशंका रहती है, अत: समय-समय पर सूतली की सहायता से बांधते रहना चाहिए।

▷पौधों के तने से निकलने वाली फुटानों समय-समय पर हटाते रहना चाहिए। साथ ही पुरानी पत्तियों को भी हटाते रहना चाहिए।

उपज: पॉली हाउस में शिमला मिर्च की फसल 8-9 महीने चलती है, एवं पौधा रोपण के 3-4 महीने बाद फल तोड़ने लायक हो जाते है। एक पौधे से 6-7 किलोग्राम तक उपज हो जाती है।

मचान पद्धति से करें सब्जियां, कम खर्च में ज्यादा उत्पादन आय होगी

भरतपुर (विसं)। सामान्यरूप से बेल वाली सब्जियों की खेती में कई तरह के कीट, बीमारियों और पर्याप्त मात्रा में रोशनी नहीं मिलने से उपज कम होती है, लेकिन अगर परंपरागत तरीके से बेल वाली सब्जियों की खेती के बजाय मचान पद्धति का उपयोग किया जाए, तो किसान अधिक उपज आय प्राप्त कर सकते हैं। मचान पद्धति से बेल वाली सब्जियों जैसे लौकी, खीरा, करेला, तोरई सेम आदि की खेती आसानी से की जा सकती है। इन सब्जियों की नर्सरी भी कम समय में आसानी से तैयार कर सकते हैं। इस पद्धति में अधिक लागत भी नहीं आती। करीब 6-6 फीट की दूरी पर 8 फीट ऊंचे डंडे या लोहे के एंगल गाड़े जाते हैं और इनके बीच तार या मजबूत रस्सी से जाल सा बना दिया जाता है ताकि सब्जियों की बेल इन पर आसानी से चढ़ सकें। इस पद्धति से बेल वाली सब्जियों की अगेती फसल भी ले सकते हैं। इससे अधिक मुनाफा कमाया जा सकता है। बेल वाली सब्जियों के लिए खेत की जुताई कर उसमें सड़े हुए गोबर की खाद डालें और उसकी पुनः जुताई कर दें। इसके बाद प्रति हैक्टेयर 240 ग्राम यूरिया, 500 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट एवं 125 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश चाहिए। नर्सरी में पौध तैयार करने के बाद इन्हें खेत में नालीनुमा आकार बनाकर निर्धारित दूरी पर लगा दें। इसके बाद लकड़ियों के डंडों या लोहे के एंगलों को 6-6 फीट की दूरी पर गाड़ दें। जैसे ही पौधों में बेल बनना शुरू होंगी तो वे इनके बीच लगे तारों से ऊपर की ओर जाने लगेंगी। पौधों की रोपाई करते समय मिट्टी से अच्छी तरह दबा दें और 20-25 दिन बाद पुनः मिट्टी चढ़ा दें। रोपाई करते समय प्रत्येक गड्ढे में 30-40 ग्राम यूरिया और 80-100 ग्राम सिंगल सुपर फास्फेट तथा 40-50 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश जरूर डालें। जैसे ही पौधों की बेलें तारों के जरिए ऊपर जाएंगी तो उन्हें पर्याप्त धूप मिलेगी और जमीन से होने वाली बीमारियों कीड़ों से सुरक्षित रहेंगी। मचान पद्धति से बोई गई बेल वाली सब्जियों में वैसे तो बीमारियां कम लगती हैं। फिर भी प्रारंभिक अवस्था में लाल कीड़ा, फल-मक्खी, मिल्ड्यू नुकसान पहुंचाते हैं। इनकी रोकथाम के उपाय करने चाहिए। मचान पद्धति से लुपिन फाउंडेशन के जरिए भरतपुर के कुम्हेर तहसील क्षेत्र के समन गांव निवासी देवकी नंदन ने सब्जियों की खेती शुरू की। इसमें उसे दोगुना तक लाभ मिला।

सहकारी गोदामों की क्षमता में एक लाख मैट्रिक टन का इजाफा

सभी समितियों में गोदाम बनाने का है लक्ष्यः सहकारिता मंत्री

जयपुर (कासं)। सहकारिता मंत्री अजय सिंह किलक ने बताया कि राज्य में किसानों की उपज के भण्डारण की समस्या को दूर करने एवं उन्हें समय पर कृषि आदानों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए हम सहकारी संस्थाओं की भण्डारण क्षमता में लगातार इजाफा कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि ग्राम सेवा सहकारी समितियों एवं क्रय-विक्रय सहकारी समितियों में विभिन्न योजना के तहत 800 से अधिक गोदामों का निर्माण कर लगभग 1 लाख मैट्रिक टन भण्डारण क्षमता सृजित कर रहे हैं। हमारी प्राथमिकता प्रत्येक ग्राम सेवा सहकारी समिति में गोदाम का निर्माण करना है वर्तमान में राज्य में 6 हजार 480 ग्राम सेवा सहकारी समितियां कार्य कर रही हैं जिनमें से 5 हजार 780 समितियों में गोदाम बना दिए गए हैं, शेष 680 समितियों को सूचीबद्ध कर लिया गया है। ऐसी समितियों में भूमि की उपलब्ध कराए जाने के लिए जिला प्रशासन के स्तर से प्रयास किए जा रहे हैं। जिन समितियों में भूमि उपलब्ध होना संभव नहीं है और विद्यालयों के परिसीमन के कारण खाली हुए विद्यालय भवन उपलब्ध हैं ऐसे भवनों को शिक्षा विभाग की सहमति से गोदाम के रूप में काम में लिया जाएगा। राज्य में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत 100-100 मैट्रिक टन क्षमता के 255 गोदाम एवं 250-250 मैट्रिक टन क्षमता के 30 गोदाम का निर्माण लगभग पूर्ण हो चुका है। सहकारिता मंत्री ने बताया कि झालरापाटन में प्रस्तावित 2500 मैट्रिक टन क्षमता के शीतगृह के निर्माण के लिए भूमि चिह्नित कर ली गई है, जिसके आवंटन की कार्यवाही करवाई जा रही है।

टमाटरों के लिए इन दिनों तैयार करें नर्सरी

अलवर (विसं)। टमाटर की गर्मी की फसल के लिए किसान इन दिनों नर्सरी तैयार कर सकते हैं। नर्सरी बनाने का काम नवंबर दिसंबर में किया जा सकता है। इसके लिए प्रति हैक्टेयर 400 से 500 ग्राम बीज की आवश्यकता होती है। संकर किस्मों के लिए प्रति हैक्टेयर 150 से 200 ग्राम बीज ही पर्याप्त होता है। कृषि विशेषज्ञों के अनुसार, एक हैक्टेयर फसल की नर्सरी तैयार करने के लिए ऊंची उठी हुई एक मीटर चौड़ी और 5 मीटर लंबी 25 क्यारियां बनानी चाहिए। बीजों को बुआई करने से पहले कार्बेन्डाजिम या थाइरम 3 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से उपचारित कर 5 से 7 सेंटीमीटर दूरी पर कतारों में बोएं। बुआई से पहले क्यारियों में 8 से 10 ग्राम कार्बोफ्यूरॉन 3 प्रतिशत कण प्रति वर्गमीटर की दर से भूमि में मिलाएं। विषाणुजनित बीमारियों की रोकथाम के लिए 40 मैश जाल का उपयोग करें।

ग्राम सेवा सहकारी समितियों का होगा कम्प्यूटरीकरण

जयपुर (कासं)। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2017-18 के केन्द्रीय बजट में 63 हजार ग्राम सेवा सहकारी समितियों का कम्प्यूटरीकरण किए जाने की योजना की घोषणा की गई है। इसके तहत राज्य की ग्राम सेवा सहकारी समितियों के रिकार्ड संधारण में सुधार करने, किसानों की साख की सुगम उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा किसानों की आवश्यकताओं का आकलन कर उनके हित में योजनाएं बनाने के लिए इन समितियों का कम्प्यूटरीकरण किया जाएगा। यह जानकारी प्रमुख शासन सचिव एवं रजिस्ट्रार, सहकारिता अभय कुमार ने दी। कुमार राजस्थान स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक लि., जयपुर स्थित सभागार में केन्द्रीय सहकारी बैंकों के कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। ग्राम सेवा सहकारी समितियों के कम्प्यूटरीकरण के लिए मापदण्ड निर्धारित किए गए हैं। जिसके अनुसार वे समितियां जिन्होंने वर्ष 2016-17 की अवधि में किसानों को कृषि ऋण उपलब्ध कराएं हों व वर्ष 2015-16 तक जिसका ऑडिट पूर्ण हो गया हो, जिनके पास स्वयं का या किराए पर पक्का कार्यालय हो एवं जिसमें पूर्णकालिक वैतनिक व्यवस्थापक कार्यरत हो इस योजना के तहत पात्रता रखती हैं। इन समितियों में दूरसंचार डाटा नेटवर्क, विद्युत शक्ति के लिए संसाधन उपलब्धता की संभाव्यता हो तथा स्थानीय स्तर पर कम्प्यूटर साक्षर व्यक्ति उपलब्ध होना चाहिए जो कि सुगमता से कम्प्यूटर ऑपरेशन को संपादित कर सके।

राज्य में 6314 ग्राम सेवा सहकारी समितियां हैं। योजना के अनुसार प्रत्येक ग्राम सेवा सहकारी समिति के कम्प्यूटरीकरण पर लगभग 3 लाख रुपए की लागत आएगी जिसमें 60 प्रतिशत राशि भारत सरकार द्वारा, 35 प्रतिशत राशि राज्य सरकार द्वारा तथा शेष 5 प्रतिशत राशि स्वयं ग्राम सेवा सहकारी समिति द्वारा वहन की जाएगी।

प्रदेश में बड़े पैमाने पर होने लगी अरंडी की खेती

भरतपुर (विसं)। जलवायु परिवर्तन से मौसम में बदलाव, निरंतर रासायनिक खादों के प्रयोग से भूमि की संरचना में आए बदलाव कृषि आदानों की बढ़ती दरों को देखते हुए किसान कम क्षेत्रफल में अधिक आय देने वाली फसलों की बुआई पर ध्यान देने लगे हैं। इनमें अरंडी की खेती अधिक उपयोगी मानी गई है। अन्य फसलों की अपेक्षा अरंडी की खेती में सिंचाई के लिए कम पानी कृषि आदानों की कम जरूरत होती है। अरंडी तेल की विश्व बाजार में बढ़ती मांग को देखते हुए अन्य तिलहनों के मुकाबले दुगने से अधिक भाव मिल जाता है। विश्व में भारत सबसे बड़ा अरंडी उत्पादक देश है। यहां उत्पादित करीब 16 लाख टन अरंडी तेल का 60 प्रतिशत भाग विभिन्न देशों को निर्यात कर दिया जाता है। भारत में अरंडी का सर्वाधिक उत्पादन गुजरात में होता है। इसके अलावा राजस्थान, आंध्रप्रदेश अन्य राज्यों में होता है। राजस्थान के बाड़मेर, हनुमानगढ़, जालौर, जोधपुर, भरतपुर सिरोही जिलों में अरंडी की प्रचुर खेती होती है। भरतपुर जिले में अरंडी की खेती लुपिन ह्यूमन वेलफेयर एंड रिसर्च फाउंडेशन संस्था ने बयाना पंचायत समिति क्षेत्र में प्रारंभ कराई है। इससे किसानों को प्रति हैक्टेयर 50 से 70 हजार रु. आसानी से मिल रहे हैं। अरंडी की बुआई सामान्य रूप से खरीफ फसलों के साथ जुलाई या अगस्त माह में की जाती है। अरंडी की जड़ें जमीन में काफी गहरी जाती है। इसलिए दो-तीन बार गहरी जुताई करनी पड़ती है। भूमि तैयार होने के बाद उन्नत किस्म के बीजों की बुआई की जाती है। इनमें मुख्य रूप से अरुणा, जी.सी.एच-3, माग्या आदि किस्में उत्तम मानी गई हैं। माग्या किस्म मुख्य रूप से 120 से 150 दिन में तैयार हो जाती है। उपज भी 20 क्विंटल प्रति हैक्टेयर से अधिक रहती है। इस किस्म में उखटा, जड़गलन, हरा तेल तथा सफेद मक्खी जैसे रोगों से भी सुरक्षित मानी गई है। अरंडी की खेती सामान्य रूप से 20 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान एवं कम आर्द्रता वाले क्षेत्रों में आसानी से होती है। इस फसल के लिए रासायनिक खादों की कम जरूरत होती है, लेकिन अधिक उपज लेने के लिए सिंचित क्षेत्रों में 40 किलो नत्रजन एवं असिंचित क्षेत्रों में 20 किलो प्रति हैक्टेयर नत्रजन का प्रयोग करना चाहिए।

सर्दियों में अमरुद की बम्पर पैदावार

बांसवाड़ा (विसं)। सर्दियों के साथ ही प्रदेश में इन दिनों अमरुद की बंपर आवक हो रही है। उत्तरी-पूर्वी राजस्थान में इसकी पैदावार अधिक होती है। कोटा उदयपुर संभाग में फरवरी-मार्च में इसके पौधे लगाए जाते हैं। बारिश के सीजन जुलाई में भी इसकी फसल आती है, लेकिन, मुख्य फसल का सीजन सर्दी ही माना जाता है। कृषि वैज्ञानिक बताते हैं कि अमरुद मुख्यतः उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में उगाए जाने वाला पौष्टिक फल है, जो शरीर के लिए काफी फायदेमंद है।

कृषि अनुसंधान केंद्र के सेवानिवृत्त निदेशक डॉ. जीएस आमेटा बताते हैं कि देश में अमरूद का सर्वाधिक उत्पादन बिहार उत्तरप्रदेश में होता है। राजस्थान में अमरुद पैदावार का क्षेत्र सीमित है, लेकिन बागवानी में रुचि रखने वाले किसान अब अमरुद की पैदावार में खासा उत्साह दिखाने लगे हैं, क्योंकि इससे आर्थिक लाभ भी होता है। संभागीय कृषि अनुसंधान केंद्र बोरवट-बांसवाड़ा के सहायक आचार्य (पौध व्याधि) डॉ. प्रशांत जांभुलकर ने बताया कि अमरुद के फलों की अधिक पैदावार लेने के लिए उखटा रोग प्रबंधन के उपाय बहुत जरूरी हैं।

प्रदेश के लिए 14 करोड़ की 36 नई परियोजनाएं मंजूर

जयपुर (कासं)। मुख्यमंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजे ने नई दिल्ली के श्रम शक्ति भवन में केंद्रीय जल संसाधन मंत्री नितिन गडकरी के साथ हुई बैठक में प्रदेश की विभिन्न जल संसाधन एवं नदी परियोजनाओं तथा राजस्थान के लिए यमुना नदी के जल संबंधी मुद्दों पर चर्चा की। केंद्रीय मंत्री गडकरी ने बताया कि राज्य की जल संसाधन से जुड़ी मरम्मत, जीर्णोद्धार तथा पुनरूत्थान की 14 करोड़ की लागत वाली 36 नई परियोजनाओं को मंजूरी दे दी गई है। प्रदेश की इन परियोजनाओं के लिए पहली किश्त शीघ्र ही जारी कर दी जायेगी।

सरहिन्द और राजस्थान फीडर के लिए 2 हजार करोड़ की जरूरत: श्रीमती राजे ने कहा कि सरहिन्द और राजस्थान फीडर के उन्नयन का काम अप्रेल 2018 तक पूरा करवाया जाना है। उन्होंने केंद्रीय जल संसाधन मंत्री से इसके लिए 2 हजार करोड़ रुपए तत्काल मंजूर किए जाने का आग्रह किया। उन्होंने राज्य की महत्वाकांक्षी परवन परियोजना की स्वीति प्रदान करने के साथ केंद्रीय मदद की राशि बढ़ाने की मांग भी रखी।

37 हजार करोड़ की ईआरसीपी परियोजना के लिए तय हो केंद्र की हिस्सेदारी: मुख्यमंत्री ने कहा कि (ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट) ईआरसीपी परियोजना के तहत प्रदेश की 40 प्रतिशत आबादी को पेयजल सुविधा और दो लाख हेक्टयर भूमि में सिंचाई के अलावा 13 जिलों की 2 लाख हेक्टयर भूमि में सिंचाई सुविधा सुलभ करवानी है।

नर्मदा एवं गंगनहर परियोजना के लिए जारी हों 328 करोड़: श्रीमती राजे ने बैठक में नर्मदा एवं गंगनहर परियोजना से जुड़ी परियोजनाओं के लिए केंद्रीय हिस्सेदारी की बकाया 328 करोड़ रुपए की राशि जारी करवाने की मांग रखी। साथ ही नर्मदा कैनाल प्रोजेक्ट के रिवीजन की स्वीकृति प्रदान करने की भी मांग की। बैठक में केन्द्रीय जल संसाधन राज्यमंत्री अर्जुनराम मेघवाल, राज्य के जल संसाधन मंत्री डॉ. रामप्रताप, सार्वजनिक निर्माण मंत्री यूनुस खान, राजस्थान नदी बेसिन एवं जल संसाधन योजना प्राधिकरण के अध्यक्ष श्रीराम वेदिरे, केंद्र सरकार के जलसंसाधन सचिव डॉ. अमरजीत सिंह और राज्य के जल संसाधन और इंदिरा गांधी परियोजना के प्रमुख सचिव शिखर अग्रवाल सहित केंद्र व राज्य के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे।

गल्होत्रा बने पुलिस के नये मुखिया

जयपुर (कासं)। भारतीय पुलिस सेवा के ओ.पी. गल्होत्रा को राज्य सरकार ने एक आदेश जारी कर पुलिस विभाग की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी है। राज्य सरकार ने गल्होत्रा को पुलिस विभाग का महानिदेशक बनाया है। चार्ज संभालने के उपरान्त प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि राजस्थान पुलिस का सदैव से ही एक गौरवशाली इतिहास रहा है, सरकार ने मुझे एक बडी जिम्मेवारी सौंपी है जो अत्यन्त गर्व की बात है। पुलिस की प्राथमिकताएं रोज नही बदलती। जनता की पुलिस से अपेक्षाएं बढी है, जनता की आशाओं पर खरा उतरना ही ध्येय है। गल्होत्रा ने कहा कि हमारी टीम अभी की सर्वोत्तम टीम है, सभी को साथ लेकर चर्चा करके पुलिस के ध्येय वाक्य 'आमजन में विश्वास-अपराधियों में भय'' की भावना को आमजन में और अधिक प्रगाढ कर सकूं इसी जिम्मेदारी के साथ कार्य करता रहूंगा। उन्होंने कहा कि पुलिस के प्रति यदि जनता का भरोसा डगमगाता है तो उसमें सुधार की आवश्यकता समझनी होगी।

सर्दियों में लगाएं फलदार पौधों के बगीचे

जयपुर (कासं)। आय बढ़ाने के लिए किसानों को परंपरागत खेती के साथ फलदार पेड़ पौधों की ओर रुख करना होगा। इसके लिए किसान फल वाले पौधों वाली नर्सरी या मातृ बगीचा (मदर गार्डनरी) लगा सकते हैं। दुर्गापुरा स्थित कृषि अनुसंधान संस्थान के उद्यान संभाग के आचार्य प्रो. सुब्रत मुखर्जी का कहना है कि फलदार पौधों से प्रति इकाई आमदनी भी अधिक होती है, जो परंपरागत खेती से मिलने वाली आय से काफी अधिक होती है।

डॉ. मुखर्जी का कहना है कि राज्य के किसानों की मांग को पूरा करने के लिए यहां किसान ही उन्नत किस्म की छोटी पौध लाकर मातृ बगीचा तैयार कर सकते हैं।

राजस्थान पर्यटन को मिला बेस्ट वेडिंग डेस्टिनेशन अवार्ड

जयपुर (कासं)। राजस्थान पर्यटन को बेस्ट वेडिंग डेस्टिनेशन अवार्ड प्रदान किया गया है। राजस्थान ने यह अवार्ड गोवा के साथ सांझा किया है। नई दिल्ली के मौर्या शेरेटन में ट्रेवल प्लस लेजर साउथ एशिया द्वारा आयोजित एक भव्य समारोह में यह पुरस्कार नई दिल्ली में राजस्थान पर्यटक सूचना केंद्र की अतिरिक्त निदेशक डॉ. गुंजीत कौर ने ग्रहण किया। समारोह में विभिन्न 50 श्रेणियों में पुरस्कार प्रदान किये गए।

उदयपुर को राष्ट्रीय स्तर पर अवार्ड

जयपुर (कासं)। झीलों की नगरी उदयपुर को पर्यटकों का पसंदीदा अवकाश स्थल होने के लिये राष्ट्रीय स्तर पर रनर अप अवार्ड प्राप्त हुआ है। नई दिल्ली के ऐरो सिटी में कॉडे नस्ट ट्रैवलर रीडर्स ट्रेवल अवार्ड द्वारा आयोजित एक समारोह में श्रीमती दिव्या थानी ने राजस्थान पर्यटक सूचना केन्द्र के छत्रपाल को उदयपुर को 'फेवराइट लेजर डेस्टिनेशन इन इंडिया' का अवार्ड प्रदान किया। इस मौके पर श्रीमती थानी ने कहा कि दुनिया भर में पूर्व का वेनिस और झीलों की खूबसूरत शहर के रूप में विख्यात उदयपुर में हर वर्ष देश विदेश के सैलानी बड़ी संख्या में भ्रमण के लिए आते हैं।

आठ जिलों में 62 नई ग्राम सेवा सहकारी समितियों का हुआ गठन

समितियों की संख्या बढ़कर हुई 6 हजार 413

जयपुर (कासं)। रजिस्ट्रार एवं प्रमुख शासन सचिव, सहकारिता अभय कुमार ने बताया कि नए वित्तीय वर्ष में अब तक राज्य के 11 जिलों में 62 नई ग्राम सेवा सहकारी समितियों व बहु उद्देश्यीय सहकारी समितियों का गठन किया गया है। इसके लिए स्वीकृति आदेश जारी कर दिए हैं। उन्होंने बताया कि चित्तौड़गढ़ जिले में 18, उदयपुर जिले में 14, अजमेर जिले में 09, जयपुर में 06, भीलवाड़ा एवं बाड़मेर जिले में 3-3, पाली, राजसमंद, नागौर एवं जोधपुर में 2-2 तथा चूरू जिले में एक नई पैक्स का गठन किया गया है।

कुमार ने बताया कि उन्होंने बताया कि इन सभी नई पैक्सों का गठन राज्य सरकार की नीति के अनुसार ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर किया गया है। राज्य सरकार की प्राथमिकता है कि अधिक से अधिक किसानों को सहकारिता के दायरे में लाया जाए एवं उन्हें सहकारी योजनाओं का फायदा दिलवाया जाए।

राज्य सरकार की इसी मंशा के मद्देनजर प्रत्येक ग्राम पंचायत में ग्राम सेवा सहकारी समिति गठित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि राज्य में अब 6413 ग्राम सेवा सहकारी समितियां हो गई हैं। प्रमुख शासन सचिव ने बताया कि चित्तौड़गढ़ जिले की गुडाखेडा, टाई, बडावली, धामंचा, सोमरवालों का खेडा, ऊंचा, मंगलवाड, पीराना, रोलाहेडा, रेवलिया खुर्द, करूकडा, लालास, अभयपुर, जलिया, रावडदा, सुखवाडा, कूंथना एवं सादी में 18 नई पैक्स, उदयपुर जिले की 14 नई पैक्स मेवाड़ों का मठ, वाना, केदारिया, बड़गांव, सवना, महाराज की खेड़ी, अमरपुरा जागीर, बालाथल, आकोला, रेवलिया खुर्द, चित्रावास, कमोल, जोधपुर खुर्द एवं अटाटिया में, अजमेर जिले की 9 केसरपुरा, सिरोज, दादिया, झीरोता, कटसुरा, गिरवरपुरा, पीपलाज, दौलतपुरा एवं करांटी में नई पैक्स खोली गई हैं।

शेखावाटी में महकने लगी केसर की खुशबू

नवलगढ़ (विसं)। जम्मू-कश्मीर जैसे ठंडे प्रदेश में पनपने वाली केसर की खेती अब शेखावाटी के धोरों में भी होने लगी है। केसर के जरिए किसानों की जिंदगी में नए रंग घोलने के लिए मोरारका फाउंडेशन आगे आया है। इसके प्रयासों से 8 किसान प्रायोगिक तौर पर इसकी खेती करने लगे हैं। सबसे पहले चेलासी गांव के किसान मुरलीधर सैनी ने केसर उगाकर उम्मीदें बढ़ाई हैं। मोरारका हवेली में भी केसर की क्यारी तैयार की गई है। कुछ पौधों में फूल भी खिले हैं। इन फूलों से केसर का उत्पादन होगा। मोरारका फाउंडेशन के स्थानीय मैनेजर अनिल सैनी ने बताया कि कश्मीर से लाए प्रमाणित बीज से खेती शुरू की गई है। सर्दी का मौसम केसर की फसल के लिए सबसे उत्तम है। दिन में धूप खिलने और रात को सर्दी पड़ने से फूल ज्यादा आते हैं। केसर के फूल रात के अंधेरे में बंद कमरे में सुखाए जाते हैं। कृषि अधिकारी इस बात का दावा करते हैं कि यहां पैदा होने वाली केसर की गुणवत्ता अच्छी नहीं हो सकती, क्योंकि श्रेष्ठ किस्म के लिए लंबे समय तक शून्य से कम तापमान चाहिए। अनिल सैनी इस दावे को खारिज करते हैं। फिलहाल मोरारका हवेली, कल्याणपुरा के रामावतार बुगालिया, बलवंतपुरा फाटक के संजू सैनी, बड़ी झींगर के ओमप्रकाश पचार, बसावा के भानाराम सैनी, बलरिया का बास के नेमीचंद धायलों का बास के बलवीर सिंह केसर की खेती कर रहे हैं।

Hindchem Corproation

☞AMINO+HUMIC SHINY BALLS ☞FERROUS SULPHATE19%
☞MAGNESIUM SULPHATE 9.6% ☞FERROUS EDTA12%
☞E.D.T.A. ACID ☞CAMPHOR ☞SODIUM BICARBONATE
☞EDTA DISODIUM ☞CITRIC ACID MONOHYDRATE
☞MANGANESE SULPHATE 30.5%
☞SULPHUR 90% -80WDG ☞BORON 20%
☞BRONOPOL 25% ☞PHOSPHORIC ACID

We Welcome Your Valuable Inquiry
Tel. 022-66998360/61
Fax-022-66450908
Email id: mamta@hindchem.com
Mo. 9004744077

16 पोषक तत्वों के बिना अधूरी है सरसों की खेती

डॉ. अशोक कुमार शर्मा, वरिष्ठ वैज्ञानिक, कृषि प्रसार, सरसों अनुसंधान निदेशालय, भरतपुर, राजस्थान

किसान भाईयो, पौधों को एक स्वस्थ जीवन पूरा करने के लिए 16 पोशक तत्वों की आवश्यकता होती है और यदि इसमें से किसी एक पोशक तत्व का भी अभाव हो जाये तो पौधे अपनी पूरी क्षमता से उपज नहीं दे पाते हैं। नेत्रजन, फास्फोरस, पोटाश और गंधक राई-सरसों फसल के प्रमुख पोषक तत्व हैं।

इन पोषक तत्वों की पूर्ति मुख्यतया उर्वरकों से की जाती है। उर्वरकों से सरसों के उत्पादन में वृद्धि तभी संभव है जब मिट्टी जाँच के आधार पर इनका समुचित मात्रा में प्रयोग किया जाय। सरसों की सिंचित फसल के लिए विभिन्न क्षेत्रों में परिस्थिति के अनुसार 80 से 125 किग्रा/हैक्टेयर तथा अधिकांश क्षेत्रों में 75 से 80 किग्रा/हैक्टेयर नेत्रजन पोषक तत्व की अनुसंशा की जाती है। चूंकि नत्रजन तत्व अधिक घुलनशील होता है इसीलिए इसकी आधी मात्रा बुवाई के समय तथा आधी पहली सिंचाई पर कलिका निकलने की अवस्था में देनी चाहिए।

फास्फोरस तत्व की 30 से 50 किग्रा मात्रा, पोटाश तत्व की 20 से 40 किग्रा और गन्धक तत्व की भी 20 से 40 किग्रा मात्रा प्रति हैक्टेयर की दर से बुवाई के पूर्व खेत में डालने की अनुसंशा की जाती है। गन्धक पोषक तत्व वाले उर्वरकों का उपयोग कर सरसों में तेल की मात्रा बढ़ाई जा सकती है। इसलिए सदा गन्धक पोषक तत्व वाले उर्वरकों जैसे- जिप्सम, सिंगल सुपर फॉस्फेट या अमोनियम सल्फेट का इस्तेमाल बुवाई से पूर्व करें।

सरसों की बारानी खेती में सिंचित फसल की तुलना में पोषक तत्वों की आधी मात्रा ही अनुसंशा की जाती है अर्थात 40 से 60 किग्रा नत्रजन, 20 से 30 किग्रा फास्फोरस, 20 किग्रा पोटाश व 20-40 किग्रा सल्फर तथा सभी पोशक तत्वों की पूरी मात्रा बुवाई के समय ही डाली जानी चाहिये।

किसान भाईयों, इस बात का ध्यान रहे कि इन पोषक तत्वों के उर्वरकों को बीज से कम से कम 2 इंच नीचे डालें, जिससे जड़ों को इनकी उपलब्धता अच्छी तरह होती रहे। किसान भाईयों, फसल की उचित समय पर बुवाई तथा सिंचाई, बुवाई के 45-60 दिन पौध बढ़वार तक खेतों को खरपतवार रहित रखना तथा लवणीय तथा क्षारीय भूमि का समुचित प्रबंधन करना कुछ ऐसी बाते हैं, जिनका उर्वरकों के प्रभावी उपयोग में बहुत महत्व है।

प्रश्नः उर्वरक प्रबंधन में टॉप डैऊसिंग क्या होता है? इसमें क्या सावधानी रखनी चाहिए?

उत्तरः किसान भाईयों, चूंकि नत्रजन पोषक तत्व बहुत अधिक घुलनशील होता है इसीलिए इसकी आधी अनुशंसित मात्रा बुवाई के समय तथा आधी पहली सिंचाई के बाद देनी चाहिए। सरसों की फसल के लिए अनुसंशित नेत्रजन की आधी मात्रा को पहली सिंचाई के बाद डालने की क्रिया को टॉप डैऊसिंग कहते हैं। नत्रजन पोषक तत्व की टॉप डैऊसिंग के लिए यूरिया खाद डाला जाता है, जिसे पहली सिंचाई के तीन-चार दिन बाद जब खेत में पैर चिपचिपाते ना हों तब बिखेर कर डालें। टॉप डैऊसिंग के लिए यूरिया खाद को खेत में सिंचाई से पहले डालना ठीक नहीं है।

प्रश्नः राई-सरसों के बीज में तेल की मात्रा बढ़ाने में किस पोशक तत्व का महत्व है और उसके लिए क्या करना चाहिए?

उत्तरः राई-सरसों के बीज में तेल की मात्रा बढ़ाने के लिए गन्धक पोषक तत्व वाले उर्वरकों का नियमित उपयोग करना चाहिए। इसलिए सदा गन्धक पोषक तत्व वाले उर्वरकों जैसे-जिप्सम, सिंगल सुपर फॉस्फेट या अमोनियम सल्फेट का इस्तेमाल बुवाई से पूर्व करें। यदि इनका उपयोग बुवाई पर नहीं किया जा सके तो सरसों की फसल के फूल की अवस्था में थायोयूरिया नामक उर्वरक के घोल का छिड़काव करें। इसके लिए थायोयूरिया नामक उर्वरक की 500 ग्राम मात्रा को 500 लीटर पानी में मिलाकर घोल तैयार कर लें और सरसों के 45 एवं 60 दिन की फसल पर छिड़काव करें। चूंकि थायोयूरिया में 42 प्रतिशत गन्धक तथा 37 प्रतिशत नत्रजन पोशक तत्व मौजूद हैं इस कारण सरसों की पैदावार तथा बीज में तेल की मात्रा बढ़ाई जा सकती है। अधिक प्रभाव के लिए थायोयूरिया का छिड़काव दोपहर बाद करना उपयुक्त रहता है।

सरसों फसल उत्पादन में विभिन्न सूक्ष्म पोषक तत्वों का प्रबंधन

सरसों के फसल उत्पादन में विभिन्न सूक्ष्म पोषक तत्वों की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। इन पोषक तत्वों की कमी से अनेक क्षेत्रों में सरसों की पैदावार प्रभावित हो रही है । सूक्ष्म पोशक तत्वों के प्रयोग से पहले मिट्टी की जाँच करा लेनी चाहिए । मिट्टी की जाँच से यह मालूम होता है कि भूमि में उपलब्ध पोषक तत्वों की कितनी मात्रा है? ताकि जिस पोषक तत्व की कमी है उसकी पूर्ती की जा सके। अधिकांश सरसों उत्पादक क्षेत्रों में आजकल जिंक तथा बोरोन मुख्य सूक्ष्म पोषक तत्व है जिनकी कमी आजकल खेतों में देखी जा रही है।

सबसे प्रमुख हैं जिंक यानी जस्ता जिसके अभाव में पौधों की बढ़वार रूक जाती है। सरसों में यह फली की संख्या बढ़ाने में सहायता करता है। प्रयोगों के आधार पर जिंक की कमी वाली मिट्टियों में जिंक को डालने पर करीब 25-30 प्रतिशत की पैदावार में वृद्धि होती है।

इसके लिए मिट्टी में बुवाई से पहले 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट प्रति हैक्टेयर अकेले या जैविक खाद के साथ प्रयोग किया जा सकता है। यह 3 से 4 फसलों तक पर्याप्त होता है। जिंक की कमी वाले क्षेत्र में यदि बुवाई से पहले जिंक सल्फेट का उपयोग नहीं किया गया है तो जिंकयुक्त रसायन का छिड़काव करें। इसके लिए 500 लीटर पानी में 2.5 किलोग्राम जिंक सल्फेट तथा 1.0 किलोग्राम बुझे हुए चूने का घोल बना लें और उसे छान कर पौधे की 30 दिन की अवस्था से 15 दिन के अन्तराल पर 2 बार छिड़काव कर सकते हैं। दूसरा सबसे प्रमुख सूक्ष्म पोशक तत्व बोरोन है जिसे हम सुहागा कहते हैं। अगर इसका अभाव हो जाये तो सरसों में फूल आने पर फलियों में दाने काफी कम हो जाते हैं। बोरोन की कमी के कारण पौधों का उपरी भाग मर जाता है और इसके पास से पत्तियाँ निकलना प्रारम्भ हो जाने से झाड़ीनुमा दिखने लग जाता है। इसके लिए 10 किलोग्राम बोरेक्स प्रति हेक्टेयर की दर से खेतों में बुवाई से पूर्व मिला दिया जाये तो अच्छा लाभ मिलता है।

प्रश्नः समेकित पोषक तत्व प्रबंधन के अंतर्गत क्या होता है?

उत्तरः समेकित पोषक तत्व प्रबंधन के अंतर्गत रासायनिक उर्वरकों का हरी खाद, गोबर की खाद, केंचुआ खाद, जीवाणु खाद आदि के साथ समन्वित उपयोग किया जाता है। समेकित पोषक तत्व प्रबंधन से भूमि की संरचना में सुधार होता है, नमी संरक्षित होती है और भूमि की उर्वरा शक्ति में बढ़ोतरी के साथ साथ उत्पादन भी बढ़ता है। फसल में खाद की मात्रा निर्धारित करने से पहले मृदा परीक्षण कराना आवश्यक है। हरी खाद में ढैंचा या सनई को वर्षा शुरू होते ही बोना चाहिए व 45-50 दिन बाद फूल आने से पहले जमीन में दबा देना चाहिये। इससे औसतन 30-40 किलोग्राम /हैक्टेयर नत्रजन मिल जाती है।

इसके अतिरिक्त लोबिया, ग्वार, उर्द या मूँग की फसल सरसों से पहले लेने पर सरसों की अच्छी उपज प्राप्त होती है। इन फसलों के बाद नत्रजन की दर में 40 किलोग्राम /हैक्टेयर तक की कमी भी की जा सकती है। गोबर की खाद से प्रमुख तत्वों के साथ-साथ सूक्ष्म पोषक तत्व भी उपलब्ध होते हैं। सिंचित क्षेत्रों के लिये 2.5-3.0 टन प्रति हैक्टेयर तथा असिंचित क्षेत्र में 1-2 टन प्रति हैक्टेयर अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद बुवाई के करीब एक माह पूर्व खेत में डालकर जुताई से अच्छी तरह मिला दें।

गोबर की खाद 2.5-3.0 टन प्रति हैक्टेयर के हिसाब से बुवाई से एक महीने पहले मिट्टी में मिलाने से हम 25 प्रतिशत अनुमोदित उर्वरक दर को कम कर सकते हैं। जैसा की आप जानते हैं की गोबर की खाद का अभाव होने से इसका प्रयोग बहुत कम हो गया है। इस परिस्थिति में हमें केंचुआ की खाद पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। केंचुआ की खाद में गोबर की खाद से 5 गुना नत्रजन, 6 गुना फास्फोरस व 11 गुना पोटाश अधिक होती है। इसकी मात्रा गोबर की खाद की मात्रा से आधी डालनी चाहिए।

इस प्रकार हम देखते हैं कि जिस तरह हम विभिन्न व्यंजनों का इस्तेमाल करने पर खाना खाने में संतुष्टि मिलती है, उसी प्रकार पौधों को भी एक अच्छे स्वस्थ जीवन काल के लिये विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है जिससे वह तो स्वस्थ रहते ही हैं साथ-साथ जो लोग उसे प्रयोग में लाते हैं वह भी स्वस्थ और परिपूर्ण जीवन व्यतीत करते हैं।

सौंफ के प्रमुख कीट, बीमारियां और उनका प्रबंधन

डॉ. मनोज कुमार जाट और डॉ प्रद्युमन नरायण दुबे
राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केन्द्र तबीजी, अजमेर-305206

सौंफ की खेती मुख्य रूप से मसाले के रूप में की जाती है। सौंफ के बीजों से ओलेटाइल तेल (0.7-1.2प्रश.) निकाला जाता है, सौंफ एक खुशबु धार बीज वाला मसाला होता है। सौंफ के दाने आकार में छोटे और हरे रंग के होते है। सौंफ का उपयोग आचार बनाने में और सब्जियों में खशबू और स्वाद बढ़ाने में किया जाता है। इसके आलावा इसका उपयोग औषधि के रूप में किया जाता है। भारत में सोंफ को राजस्थान (सिरोही, टोंक, अजमेर), आंध्रप्रदेश, पंजाब, उत्तरप्रदेश, गुजरात, कर्नाटक और हरियाणा के भागों में उगाया जाता है।

छाछिया रोग: यह रोग कवक से होता है। इस रोग में पत्तियों, टहनियों पर सफेद चूर्ण दिखाई देता है जो बाद में पूर्ण पौधे पर फैल जाता है। अधिक प्रकोप से उत्पादन एवं गुणवता कमजोर हो जाते हैं।

रोकथाम: गन्धक के चूर्ण 20-25 किलोग्राम/हेक्टेयर का भुरकाव करें या घुलनशील गंधक 2 ग्राम/लीटर पानी और केराथेन का 1 मि.ली/प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। आवश्यकतानुसार 15 दिन बाद में छिड़काव को दोहरावें।

जड़ एवं तना गलन: यह रोग बी कवक से होता है। इस रोग के प्रकोप से तना नीचे मुलायम हो जाता है व जड़ गल जाती है। जड़ों पर छोटे-बड़े काले रंग के स्कलेरोशिया दिखाई देते है।

रोकथाम: बुवाई से पहलें बीज को कार्बेण्डाजिम 2 ग्राम/किलो बीज की दर से बीजोपचार कर बुवाई करनी चाहिये और केप्टान 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से भूमि उपचारित करना चाहिये। ट्राइकोडर्मा विरिडी 2.5 किलो/हैक्टेयर गोबर के खाद में मिलाकर बुवाई पूर्व भूमि में डालने चाहिए।

झुलसा रोग: सौंफ में झुलसा रोग बी कवक से होता है। रोग के सबसे पहले लक्षण पौधे भी पत्तियों पर भूरे रंग के धब्बों के रूप में दिखाई देता है। बाद में ये काले रंग में बदल जाते है। पत्तियों से वृत, तने एवं बीज पर इसका प्रकोप बढ़ता है। संक्रमण के बाद यदि आर्द्रता लगातार बनी रहें तो रोग उग्र हो जाता है। रोग ग्रसित पौधों पर या तो बीज नहीं बनते या बहुत कम और छोआकार के बनते है।

रोकथाम: स्वस्थ बीजों को ही बुआई के काम में लेना चाहिए। फसल में अधिक सिंचाई नही करें। इस रोग के लगने की प्रारम्भिक अवस्था में फसल पर मेंकोजेब 0.2 प्रतिशत के घोल का छिड़काव करें आवश्यकतानुसार 10 से 15 दिन बाद छिड़काव दोबारा करे।

सौंफ की फसल में गमोसिस रोगों का प्रकोप भी बहुत होता है जिससे उत्पादन एवं गुणवता गिर जाती है। रोग रहित स्वस्थ बीज को ही बोयें।

कीट प्रबंधन:

माहू व पत्ती खाने वाले कीट: इनके नियंत्रण के लिए डाइमिथोएट 30 ई.सी. एक मिलीलीटर प्रति लीटर पानी का घोल बनाकर और थाओमेथोक्षम एक मिलीलीटर प्रति लीटर पानी का घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए।

विधानसभाध्यक्ष ने काश्तकारों को चैक वितरित किए

शाहपुरा (विसं)। राजस्थान विधानसभाध्यक्ष कैलाश मेघवाल ने भीलवाड़ा जिले के शाहपुरा में ग्राम सेवा सहकारी समिति शाहपुरा द्वारा आयोजित ऋण वितरण कार्यक्रम में समिति के सदस्यों को चैक वितरित किए। उन्होंने सहकारी समिति शाहपुरा में काश्तकारों को बिना ब्याज सरकार द्वारा रुपए दिए जाने की योजना का शुभारंभ करते हुए 10-10 हजार के चेक काश्तकारों को दिए।

समिति अध्यक्ष राजेन्द्र बोहरा ने समिति के कामकाज के बारे में प्रकाश डालते हुए मेघवाल का स्वागत किया और बताया कि किसानों को रबी फसल के लिए बिना ब्याज के ऋण तथा खेती-बाड़ी की योजनाओं का प्रत्यक्ष लाभ पहुंचाने की दिशा में समिति निरन्तर प्रयत्नशील रही है। कैलाश मेघवाल ने खान्या के बालाजी मन्दिर का शिलान्यास किया। पं.भैरूलाल शास्त्री के आचार्यत्व में विधिविधान से पूजा-अर्चनापूर्वक भूमि पूजन हुआ। इस अवसर पर विधानसभाध्यक्ष मेघवाल, सांसद सुभाष बहेड़िया एवं मन्दिर के महंत रामदास त्यागी ने संबोधित किया।

कृषि सलाह
किसान भाई ध्यान देवें

सरसों: सरसों की फसल में मोयला कीट के प्रकोप पर नजर रखे । मोयला कीट का प्रकोप दिखाई देते ही मिथाइल पैराथियॉन 2 प्रतिशत चूर्ण का 25 किलो प्रति हैक्टेयर की दर से भुरकाव करे ।

फूल गोभी एवं पत्ता गोभी: फूल गोभी एवं पत्ता गोभी में आरा मक्खी,पत्ती भक्षक लटें, एवं गोभी की तितली का प्रकोप दिखाई देने पर मैलाथियॉन 5 प्रतिशत या कारबोरिल 5 प्रतिशत चूर्ण का 20-25 किलो प्रति हैक्टेयर की दर से भुरकाव करें या मैलाथियॉन 50 ई.सी. एक मि.ली. का प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव करें ।

गेहूं: गेहूं की बुवाई करें । राज. 4079, राज. 4120, राज. 4037, राज. 6560 एवं राज. 3765 इस संभाग के लिये गेहूं की उन्नत किस्में हैं । बुवाई हेतु 100 किलो बीज प्रति हैक्टेयर प्रयोग में लेवे तथा कतार से कतार की दूरी 20 या 22.5 से.मी. रखें । बीजोड़ रोगों से बचाव हेतु 2 ग्राम थाइरम या 2.5 ग्राम मैन्कोजेब का प्रति किलो बीज की दर से उपचारित करें। जिन खेतों में अनावृत कण्डवा एवं पत्ती कण्डवा रोग का प्रकोप हो वहाँ नियंत्रण हेतु कार्बोण्डेजिम 2 ग्राम का प्रति किलो बीज की दर से बीजोपचारित करें। दीमक के नियंत्रण हेतु 4.5 मि.ली. क्लोरपाइरीफॉस 20 ई.सी. अथवा फिप्रोनिल 5 एस. सी. 6 मि.ली. प्रति किलो बीज की दर से अथवा क्लोथिएनिडीन 50 डब्लू डी. जी. 1.5 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से आवश्यकतानुसार पानी में घोल बनाकर बीजों पर समान रूप से छिड़क कर उपचारित करें एवं छाया में सुखाने के बाद बुवाई करें । बीजोपचार के 2 घंटे के अंदर बुवाई करें । अन्त में एजेक्टोबेक्टर कल्चर के 3 पैकिट से एक हैक्टेयर क्षेत्र के बीजों को उपचारित करें। बीजोपचार में फफूंद नाशी, कीट नाशी कल्चर (एफ.आई.आर) का क्रम रखें । बुवाई के समय प्रति हैक्टेयर 45 किलो नत्रजन व 20 किलो फॉस्फेट ऊर कर देवे ।

गाय एवं भैंसों: दुधारु गाय एवं भैंसों में दूध दुहने के बाद थनों को गीला नही छोड़े । ठण्ड बढ़ने के साथ थनों में गीलापन छोड़ने के कारण थनैला रोग की सम्भावना बढ़ जाती है । अत: पशु का सर्दी से बचाव करें तथा दूध दुहने के बाद थनों को पोंछ देवे तथा पशु घर में साफ-सफाई का ध्यान रखें ।

सृष्टि एग्रो परिवार आपका स्वागत करता है

सदस्यता फार्म

सदस्य का नाम : ....

संस्था का नाम : ....

पूरा पता : ....

ग्राम : ....तहसील ....

जिला .... राज्य .... पिन कोड ☐☐☐☐☐☐

दूरभाष कार्य : .... निवास ....

सदस्यता राशि

एक वर्ष : 151 ☐ तीन वर्ष 351 ☐ पांच वर्ष 501 ☐

कृपया हमें/मुझे सृष्टि एग्रो की सदस्यता प्रदान कर नियमित रूप से उक्त पते पर पत्रिका भेजने की व्यवस्था करें।

सदस्यता राशि नकद/मनीऑर्डर/चेक/डिमांड ड्राफ्ट द्वारा राशि रुपए (अंकों में) शब्दों में ....

बैंक का नाम .... ड्राफ्ट चेक क्रमांक .... दिनांक ....

स्थान .... प्रतिनिधि का नाम .... हस्ताक्षर सदस्य ....

दिनांक ....

सृष्टि एग्रो

ग्रामीण विकास का सम्पूर्ण पाक्षिक समाचार पत्र

307, लिंकवे इस्टेट, लिंक रोड मालाड़ (प), मुंबई-400064 Tel. 022-66998360/61, Fax : 022-66450908,
E-mail : info@srushtiagronews.com, website : www.srushtiagronews.com

एवं हस्ताक्षर एवं संस्था सील

मूंग खरीद के लक्ष्य में हुई वृद्धि, अब 2.74 लाख मैट्रिक टन की होगी खरीदः किलक

जयपुर (कासं)। सहकारिता मंत्री अजय सिंह किलक ने बताया कि राज्य सरकार के आग्रह पर भारत सरकार द्वारा राज्य में मूंग की समर्थन मूल्य पर खरीद के लक्ष्य में 1.24 लाख मैट्रिक टन की वृद्धि कर दी है। उन्होंने बताया कि अब 2 लाख 74 हजार मैट्रिक टन मूंग की खरीद की जाएगी। किलक ने बताया कि राज्य में मूंग की बम्पर उपज को देखते हुए एवं किसानों को अधिक से अधिक लाभान्वित करने के उद्देश्य से भारत सरकार से मूंग की खरीद के लक्ष्यों को बढ़ाने के लिए निरन्तर प्रयास किए जा रहे थे। हमने भारत सरकार के समक्ष राज्य का पक्ष मजबूती से रखा उसके उपरान्त भारत सरकार ने राज्य में मूंग खरीद के लक्ष्यों में वृद्धि की है। उन्होंने भारत सरकार द्वारा मूंग खरीद के लक्ष्य में वृद्धि पर संतोष करते हुए बताया कि नए लक्ष्यों से हम अधिक किसानों से उनकी गाढ़े पसीने से उपजाई मूंग को खरीद कर उन्हें संबंल प्रदान कर सकेंगे।

दलहन एवं तिलहन की खरीद होगी 6.34 लाख मैट्रिक टनः उन्होंने बताया कि राज्य में दलहन एवं तिलहन की समर्थन मूल्य पर खरीद के नए लक्ष्यों के अनुसार अब 1527 करोड़ रुपए की 2.74 लाख मैट्रिक टन मूंग, 324 करोड़ रुपए की 60 हजार मैट्रिक टन उड़द, 457.50 करोड़ रुपए की 1.50 लाख मैट्रिक टन सोयाबीन एवं 667.50 करोड़ रुपए की 1.50 लाख मैट्रिक टन मूंगफली की खरीद की जाएगी। उन्होंने बताया कि इस प्रकार राज्य में 2976 करोड़ रुपए की कुल 6.34 लाख मैट्रिक टन की दलहन एवं तिलहन की खरीद की जाएगी।

नागौर जिले में और बनाए 5 मूंग खरीद केन्द्रः किलक ने बताया कि इस बार नागौर जिले में मूंग की पैदावार अधिक हुई है जिससे नागौर जिले में ऑनलाइन पंजीयन कराने वाले किसानों की संख्या अधिक होने तथा पूर्व में स्थापित किए गए खरीद केन्द्रों पर कांटों की संख्या में अब इजाफा किया जाना संभव नहीं होने के कारण जिले में मूंग की खरीद हेतु 5 नए केन्द्र स्थापित किए हैं। नागौर जिले में चिमराली, रियांबडी, निमोद, नागौर भण्डार एवं मेड़ता में नए केन्द्र बनाए हैं।

अब नागौर जिले में मूंग के खरीद केन्द्रों की संख्या बढ़कर 14 हो गई है। प्रमुख शासन सचिव एवं रजिस्ट्रार, सहकारिता अभय कुमार ने बताया कि राज्य में अबतक 3 लाख 32 हजार 316 किसानों ने समर्थन मूल्य पर अपनी दलहन एवं तिलहन की उपज को बेचने के लिए ऑनलाइन पंजीयन करवाया है।

अब तक एक हजार करोड़ से ज्यादा की खरीद

सहकारिता मंत्री ने बताया कि राज्य में अब तक 1 लाख 3 हजार 986 किसानों से लगभग 1 हजार करोड़ रुपए से अधिक की मूंग, उड़द, सोयाबीन एवं मूंगफली की खरीद की जा चुकी है तथा 741 करोड़ रुपए का भुगतान उनके खातों में ट्रांसफर किया जा चुका है जो कुल खरीद का 74 प्रतिशत है। उन्होंने बताया कि किसान के सही खाते में ही राशि ट्रांसफर की जाए इसको सुनिश्चित किया जा रहा है। इसके लिए किसान द्वारा ऑनलाइन पंजीयन के समय दिए गए बैंक खाते पर भुगतान से 48 घण्टे पूर्व तथा भुगतान के बाद पंजीकृत मोबाइल नम्बर पर संदेश भेजे जा रहे हैं।

राज्य कर्मचारियों को सरकार ने दी सौगात, 3 किश्तों में मिलेगा एरियर

जयपुर (कासं)। राज्य कर्मचारियों को सातवें वेतनमान का एरियर तीन किश्तों में मिलेगा। पहली किश्त का भुगतान अप्रैल 2018 में होगा। इस परिलाभ से करीब आठ लाख पचास हजार कर्मचारी और तीन लाख 77 हजार पेंशनर्स लाभान्वित होंगे। इसका राज्य सरकार पर दस हजार 400 करोड़ का वार्षित वित्तीय भार आएगा। उद्योग मंत्री राजपाल सिंह शेखावत और राज्य वित्त आयोग की अध्यक्ष डॉ. ज्योति किरण ने सचिवालय में प्रेस वार्ता में यह घोषणा की। राज्यकर्मचारियों को सातवें वेतनमान का परिलाभ एक जनवरी 2017 से दिया जाएगा। कर्मचारियों को कुल एरियर का 30 फीसदी पहली किश्त के रुप में अप्रैल 2018 में और 30 फीसदी एरियर दूसरी किश्त जुलाई तथा शेष बचा 40 फीसदी एरियर अक्टूबर 2018 में दिया जाएगा। अब न्यूनतम वेतन 6 हजार 900 के स्थान पर 17 हजार 700 रुपए प्रतिमाह किया गया है। कर्मचारियों को सातवें वेतनमान का लाभ दिए जाने पर न्यूनतम 14.22 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और मूल वेतन में यह वृद्धि 32 प्रतिशत है।

जुलाई में वेतन वृद्धिः शेखावत ने बताया कि राज्य कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता मूल वेतन का 8 प्रतिशत एवं 16 प्रतिशत कर दिया गया है। विद्यमान कर्मचारियों का वेतन निर्धारण मूल वेतन के 2.57 के गुणक से किया गया है। वार्षिक वेतनवृद्धि प्रति वर्ष एक जुलाई को मूल वेतन की 3 प्रतिशत दी गई है।

सृष्टि एग्रो

विज्ञापन हेतु सम्पर्क करें
मोबाइल : 7728897568
jaipur@srushtiagronews.com

विज्ञापन मात्र एक कॉल की दूरी पर

उदित ओवरसीज प्रा.लि.

राजस्थान सरकार द्वारा उर्वरक अब मान्यता प्राप्त दरों व अनुदान पर उपलब्ध

फर्टिलाइजर

1. जिंक सल्फेट 21 प्रश.
2. जिंक सल्फेट 33 प्रश.
3. फेरस सल्फेट 19 प्रश.
4. कॉपर सल्फेट 24 प्रश.
5. मैग्नीशियम सल्फेट 9.6 प्रश.

बायो फर्टिलाइजर

1. राइजोबियम पाउडर
2. एजेटोबेक्टर पाउडर
3. पी.एस.बी. पाउडर

FERTILIZER

- SRUSHTI HIZINC (MICRONUTRIENT MIXTURE)
- ZINC EDTA 12%
- FERROUS EDTA 12%
- BORON 20%
- COPPER SULPHATE 24%
- SULPHUR 90% WG

BIO FERTILIZERS

- MYCORRHIZA (ROOTS GOLD)
- AZOSPIRILLUM
- PHOSPHATIC SOLUBILISING BACTERIA (PHOS UP)
- POTTASIUM MOBILIZING (POTA RISE)

WELCOME INQUIRY Contact : 7975653498 (Rajesh Sharma)

137, Industrial Area Dehra, Tehsil Chomu, Dist, Jaipur

स्वामी : सुरेश जी. शर्मा, प्रकाशक एवं मुद्रक विकाश शर्मा की ओर से जयपुर प्रिंटर्स, सी-565, 4-सी स्कीम न्यू लोहामण्डी रोड, सीकर रोड जयपुर से मुद्रित किया गया और प्लाट नं. बी-82 नीलगिरी कॉलोनी, नई अनाज मंडी के पीछे, विश्वकर्मा एरिया, जयपुर 302039 यहां से प्रकाशित किया। सम्पादक : सुरेश जी. शर्मा सत्यापित शीर्षक क्रमांक RAJHIN/2014/58645 : Tel. 0141-3130277, Mob. 7728897568, E-mail : jaipur@srushtiagronews.com